[Shri Morarji Desai]

knew that I was here in the House. Then they made a demonstration. Nobody prevented them from doing it.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): May I rise on a point of order? Sir, it is for your consideration whether a matter concerning the staging of a demonstration can be a subject under Rule 377. There can be demonstrations galore everyday. Would the Chair be in order to permit a subject to be raised if there has been a demonstration staged at any Minister's place? If that is the pleasure of the Chair then, I think, the Chair is going to be flooded with requests under Rule 377.

(v) Reported retrenchment of the "Mazdoors" in Andaman and Nicobar Islands.

SHRI MANORANJAN BHAKTA (Andaman and Nicobar Islands): I like to draw the attention of this House and the Government to the reported planned retrenchment of the NMR Mazdoors from the Public Works Department and Electricity Department in the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands. In the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands, the Government is the main employer employing approximately 25 thousand Majdoors which covers almost one-third of the territories population scattered in the different Islands inside the dense forest. Development work is going on in the Islands. The Mazdoors have come there from the various parts of the country particularly from Kerala, Tamil Nadu, Andhra, Bihar etc., and under ardous nature of conditions they have spent the best part of their life. The present Government is against any kind of retrenchment. The Prime Minister is also sympathetic for rural employment. At this stage any rerenchment of Mazdoors will be against the spirit of the present Government.

I therefore, like to draw the attention of Hon'ble Home Minister who is directly incharge of the Union Territories, to kindly see that in these critical days not a single mazdoor is retrenched. The tactics of transferring one Division to other Division should restore the seniority of their services.

Further, the person already retrenched should be reinstated. This small far flung territory situated in a strategic position deserves sympathetic consideration from the Government.

MR. SPEAKER: Now, we break for lunch. After the lunch Mr. Mangal Deo will continue with his speech.

13.00 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Four Minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

MOTION RE TWENTIETH, TWENTY-FIRST AND TWENTY-SECOND REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHERULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Mangal Deo may continue his speech.

श्री मंगलदेव (भ्रकबरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल खेत मजदूरों के संबंध में चर्चा कर रहा था । बेकारी और बरोजगारी पर इस सदन में काफी चर्चा हो चुकी है । इसलिए उस में मैं बहुत नहीं जाऊंगा । आप के द्वारा एक निवेदन सरकार से करूंगा कि गरीब को जमीन नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, व्यापार नहीं मिलता तो फिर अपना जांगर बेचने के लिए तैयार होता है । गांवों से भाग भाग कर हजारों लोग शहर में आ जाते हैं और शहर में भी काम नहीं मिलता । आप ने देखा होगा न केवल छोटे शहरों में, बल्कि बड़े

शहरों में भी नुक्कड़ों पर, चौराहों पर, सैकड़ों लोग दोपहर तक खड़े रहते है जांगर बेचने के लिए। जांगर जब नहीं बिकता है तो उसे खून बेचने के लिये मजबूर होना पड़ता है। पिछले दिनों माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री राजनारायण जी ने यह स्वीकार किया था कि रोटी के लिये, बच्चों के पालन के लिये, शाम को चूल्हा जलाने के लिये आदमी अपना खून बेच कर, कुछ पैसा ले जाकर अपनी जिन्दगी को कम करता है। यह कौन सा प्लानिंग है, कौन सी व्यवस्था है कि जांगर खरीदने वाला कोई नहीं है, लेकिन खून खरीदने के लिये सारे इन्तजाम है, ब्लड-बैंक बने हुए है। मेरा आप के द्वारा चौधरी साहब से निवेदन है कि खून बेच कर पैसा लेने वाली इस व्यवस्था को हमेशा के लिये बन्द किया जाए। हमें अपने दोस्तों के लिये, रिश्तेदारों के लिये, खून की जरूरत है तो हम अपना खून दें, लेकिन सामंतवादी व्यवस्था के लोग, पैसे वाले लोग अपना खून नहीं देना चाहते, उन के पास पैसा है इसलिये गरीब का खून खरीदने के लिये तैयार है, गरीब को काम देने के लिये तैयार नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा—यह बड़ी खतरनाक बात है, बड़े शर्म की बात है मैं चाहता हूं कि गरीब का जांगर बिके, लेकिन खून नहीं। गरीब की ठठरी में दो बूंद खून है, पैसे वाले आदमी अपने पैसे के बल पर उस को भी निकाल कर अपने बच्चे, अपनी औरत या अपनी जिन्दगी को बचाने की कोशिश करते है—यह शर्मनाक व्यवस्था तुरन्त बन्द होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में ऐसी व्यवस्था भी है कि पैसे वाले आदमी पैसे के बल पर आदमी की गर्दन पर चढ़ कर घूमते हैं। पहाड़ी इलाकों में जा कर देखिये, मैंने नैनीताल में देखा—चार आदमियों के कन्धों पर एक आदमी ले जाया जा रहा था। मैंने पूछा—क्या तबियत खराब है ? उस ने कहा—नहीं, तबियत तो ठीक है। उस ने सिगरेट जलाई और धूआं फूंका। 20–20 आना दे कर चार आदमियों के कन्धों पर बैठ कर वह ननीताल की हवा खा रहा था। यह कितनी शर्मनाक बात है।

पिछले 20 सालों में गांवों में उद्योग धन्धों के लिये कई योजनायें बनाई गई। कुटीर-उद्योग के नाम पर, समाज कल्याण और हरिजन कल्याण के जो भी महकमे हैं, वे क्या अनुदान देते हैं—आप जरा देखिये। बकरी पालने वाले को 250 रुपया, सूअर के लिये 300 रुपया, पूनी के लिये, साइकल मरम्मत के काम के लिये पैसा देते है, लेकिन यह कौन सा ओरिजनल रोजगार है ? आप उन को बड़े-बड़े अनुदान या लोन क्यों नहीं देते है ? दूध का जानवर पालने के लिये पैसा दीजिये, कपड़े की दुकान खोलने के लिये पैसा दीजिये, अनाज के व्यापार के लिये पैसा दीजिये, लेकिन दिमाग में तो यह भरा हुआ है कि ये सब काम उन गरीबों के लिये नहीं है।

1972 में उस के आवास के लिये केन्द्रीय सरकार ने एक योजना बनाई। क्या कल्पना थी ? भूमिहीन खेत मजदूर के पास यदि मकान बनाने के लिये जमीन नहीं है तो उस को 100 वर्ग गज जमीन दी जायेगी। जिन के पास तीन-तीन बीघे में मकान हैं, डेढ़-डेढ़ बीघे में मकान है, दस-दस बिस्वे में मकान है, उन सामन्ती प्रवृत्ति के लोगों ने इन के लिये 100 वर्ग गज जमीन की कल्पना की थी। वे समझते हैं कि खेतिहर मजदूर को शायद चारपाई की जरूरत नहीं है, उस के पास उस के रिश्तेदार नहीं आयेंगे, वह धीरे-धीरे चलेगा, लेट कर निकलेगा—इस लिये केवल 100 वर्ग गज की कल्पना थी। उसे जोतने के लिये जमीन नहीं दी, खेती के लिये जमीन नहीं दी, लेकिन बसने के लिये 100 वर्ग गज देने का इन्तजाम सरकार की तरफ से 1972 में हुआ था। 1960 में केन्द्रीय सरकार ने अनुमान लगाया था कि लैंड-रिफार्म से 6 करोड़ 30 लाख एकड़ जमीन

[मंगल देव]

मिलेगी । उस के बाद 1970-71 में दाण्डेकर आयोग ने अनुमान लगाया कि 4 करोड़ 20 लाख एकड़ जमीन मिलेगी । उस के बाद 1972 में कृषि मंत्री ने अनुमान लगाया कि चार करोड़ एकड़ जमीन मिलेगी । उस के बाद 1975 में शासन ने अनुमान लगाया कि 37 लाख एकड़ जमीन मिलेगी, फिर 1975 में कृषि मंत्री का जवाब राज्य सभा में आया कि 9 लाख एकड़ जमीन मिलेगी और कल्पना करते करते वह 6 करोड़ 20 लाख एकड़ जमीन रह गई । इसलिए ये अनुमान पर आधारित सारे आंकड़े गलत हैं और इन से गरीब को थका डालने की बात की गई है । आप रोज इस तरह की बातें करते हैं कि हम गरीबों को जमीन देंगे, सीलिंग की बात रोज की जाती है और वह जमीन कहां से मिलेगी ? वह ग्राम सभाओं की जमीन होगी, चकबन्दी से बचत की जमीन होगी, जंगल से जमीन मिलेगी, नदी की छोड़ी जमीन होगी, नाबल्द खाते की जमीन होगी और सीलिंग की जमीन होगी । इस से लोगों में बड़ा भ्रम होगा । लोग यह सोचते होंगे कि जो जमीन मिलेगी, वह अनुसूचित जतियों के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को दी जाएगी लेकिन मैं आप को बताना चाहता हूं कि उन को जमीन देने के मामले में क्या वरीयता दी गई है । अनुसूचित जातियों का छठा नम्बर है । यह कहा जाता है उन को जमीन देने का इरादा है । जब छठे नम्बर पर उन का स्थान है, तो फिर कैसे जमीन पाने के मामले में उन का नम्बर आएगा । इस का मतलब तो यह हुआ कि खाने-पीने की जो जूठन होगी, वही उन को मिलेगी । जमीन पहले किस को मिलेगी, यह मैं आप को बताता हूं । जमीन देने की जो वरीयता निर्धारित की गई है, वह इस प्रकार है :

(1) कृषि विषय में प्रशिक्षण देने वाली मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था ।

(2) युद्ध में वीरगति को प्राप्त सैनिक के भूमिहीन आश्रित ।

(3) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन के फलस्वरूप हुए भूमिहीन व्यक्ति ।

(4) भूमिहीन सैनिक जो अधिकारी न हों ।

(5) भूमिहीन राजनैतिक पीड़ित जिन्हें पेंशन न मिली हो ।

(6) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जति के भूमिहीन खेतिहर मजदूर ।

इस तरह से आप देखें कि इन पांचों केटेगिरीज को जमीन मिलने के बाद अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का नम्बर आता है । इसलिए मेरा कहना यह है कि उन के लिए जमीन देने का सवाल ही नहीं है । उन को जमीन कहां से मिलेगी । सन् 1950 में जमींदारी टूटी और उस में जो जमीन मिली, उस में कितनी लौट गई, इसके आंकड़े भी मैं आप को दे दूं । ये आंकड़े उत्तर प्रदेश के हैं । सीलिंग की जमीन जिस पर कब्जा लिया गया था वह 2 लाख 1 हजार एकड़ थी । भूमि का जो बंदोबस्त किया गया, वह इस प्रकार था:

	एकड़
(1) काश्तकारों के साथ स्थायी बंदोबस्त	14,000
(2) काश्तकारों के साथ अस्थायी बंदोबस्त	76,000
(3) विभिन्न संस्थाओं के साथ बंदोबस्त	20,000
कुल	1,10,000

इस तरह से आप देखें कि 1 लाख 10 हजार एकड़ जमीन वापस चली गई । मुझे मौका

होता, तो मैं और भी आप को बताता लेकिन समय नहीं है इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश की ही बात आपको बताई है । इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि सारे देश में इसी तरह से जमीन वापस लौट गई है और मैं ऐसा समझता हूं कि जमीन बांटने का उन का कोई इरादा नहीं था । 3 जनवरी, 1960 को जो जमीन निकल जानी चाहिए थी, वह जमीन आज तक नहीं निकली । बड़े फार्मों का हिस्सा बना हुआ है और बहुत से ऐसे कानून बने हुए हैं जिन के कारण 3 हजार केसेज हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं । इसलिए मैं यह कहता हूं कि यह सब सालबट्टा है और सीलिंग में जो इन लोगों को जमीन देने की बात कही गई है, वह सब धोखाधड़ी है । एक तरफ तो लाखों आदमियों को आश्वासन देते हैं कि इतनी जमीन निकलेगी और उस में हम जमीन देंगे लेकिन उतनी जमीन निकलती नहीं है । अगर जमीन निकलती भी है तो गांव के सामंती और विरोधी लोग, उसको ले लेते हैं । उत्तर प्रदेश में चौधरी साहब जानते हैं कि कितनी जमीन निकली है । इनके समय में यह हुआ था और इन्होंने काफी जमीन निकाली थी जिस में से 115 लाख एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश में गांव सभाओं को मिली और 22 लाख एकड़ जमीन जंगल विभाग को दी गई थी कि जंगल लगाएं । इस सारे मामले को देखते हुए, आप के द्वारा मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वह इस सारे मामले की जांच कराए । सरकार इस बात को जानती है कि सीलिंग में जाल-बट्टा और बेईमानी हुई है और जो भी आंकड़े दिये गये हैं वे गलत हैं । इसलिए मैं कहता हूं कि एक पावरफुल आयोग का गठन किया जाए और तीन महीने के लिए या छः महीने के लिए उस को यह काम दिया जाए और सदन के लोग उसमें हों । अगर यह अव्यवहारिक हो, तो कोई दूसरी व्यवस्था हो । मैं कहता हूं कि जमीन के प्रश्न को हमेशा हमेशा के लिए तो आप हल नहीं कर सकते लेकिन मैं अनुरोध करता हूं और सूचना देता हूं कि जमीन के बदले कुटीर उद्योग की बात कह कर इस को न टाला जाए । जमीन से उन की जिन्दगी का नाता है और पिछले 30 वर्षों में कुटीर उद्योग उन के घर में नहीं पहुंचा है, और न उन के दरवाजे की जमीन उन्हें मिली है ।

जमीन के मामले को हमारे चौधरी साहब औरों से ज्यादा जानते हैं और मैं उन से अनुरोध करूंगा कि वे इस बारे में उचित कार्यवाही करें और इस सारे जाल-बट्टे को खत्म करने के लिए प्रभावशाली कानून बनाएं जो सारे देश पर लागू हो । राज्य सरकारों ने अपने को चलाने के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए सीलिंग एक्ट का फाड किया है । साल साल भर उस को रोक रखा है और तारीखें बदली हैं और संशोधित बिल को वापिस किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का समय दिया और आप के द्वारा मैंने मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की ।

SHRI KUSUMA KRISHNA MURTHY (Amalapuram): Mr. Deputy-Speaker, Sir. I rise to offer some of my observations on the 20th, 21st and 22nd reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. My observations mainly deal with two important aspects, namely, the justification of this Commission and its work and secondly, the attitude of the Government towards this commission and its reports.

The Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes was constituted on the 18th November, 1950 under the Article 338 of our Constitution. So far, 22 voluminous Reports have been submitted to the Government and 19 of them have already been discussed on the floor of this House. It was in November, 1972 that the 19th Report was discussed in this

[Shri Kusuma Krishna Murthy]

House. Later this practice was abandoned, and I do not know the reasons for that but I am really happy that the hon. Home Minister has revived this practice now.

The 20th Report relates to the year 1970-71, 21st Report relates to the years 1971-72 and 1972-73 and the 22nd Report relates to the year 1973-74. In a way, I have gone through these reports. These repores are highly informative, they contain apt citation splendid condification and laborious reproduction, but I believe, this Commission has lost its noble mission in these details.

The real problems of the scheduled castes and scheduled tribes has not been properly explained in these reports and similarly concrate solutions have also not been offered, in Order to enable the Government to understand the impending problems and solve them. In its task, the commission should have explained clearly and also categorised what are the urgent problems, short-term problems and long-term problems, because no Government will be able to solve all the problems on the same footing. I am aware that the constitutional responsibility of this commission is to "investiate all the matters relating to the safeguards provided for the Scheduled castes and Scheduled tribes and to report on the working thereof to the President", but that does not mean that the Commission should confine itself alone to the task of collecting the data and interpreting it. Better for the Commission to clearly understand the nature of this problem which is more a social problem rather than a mere economic problem.

Regarding the attitude of the Government in relation to this Commission and its reports, I would like to mention that we are aware that 22 Reports have already been submitted by this Commission to the Government and 19 of them have already been discussed on the floor of this House. Therefore, the Government are fully aware of the total condition of the scheduled castes and scheduled tribes in India today. But I am at a loss to understand as to why their total condition in relation to the rest of the society in this country is slowly deteriorating to the level of the state of nature, where man was "solitary, nasty and brutish," where "the might was the only right."

Yesterday, an hon. Member from the other side, namely Shri Kanwar Lal Gupta, while speaking on this issue has clearly mentioned that these people have been provided with huge funds and there are constitutional provisions like the Articles 16, 46, 335, and 338, for their exclusive betterment.

Now, I would like to concentrate on these constitutional aspects to analyse these provisions and their implications and their real effect on these classes of people at large.

The first constitutional Amendment Act of 1951 adding clause 4 to the Article 16 passed by the Parliament in order to ensure that what is guaranteed in Article 46 is made enforceable through a court of law.

This Amendment provided for discrimination in favour of backward classes. This was upheld by some of the judgements of the Supreme Court and one of the significant judgments, I would like to cite here. The Supreme Court in 1968 in the case of State of Punjab *vs.* Hiralal and others had clearly observed that "it is true that every reservation under Article 16(h) does introduce an element of discrimination particularly when the question of romotion arises. But then, the Constitution makers have thought it fit in the interest of the society as a whole that the backward class of citizens of this country should be afforded certain protections." It went on to say further that "it cannot be denied that unaided many sections of this country cannot compete with the advance sections of the nation. Advantage secured due to historical reasons should not

be considered as fundamental rights. Nations's interest will be best served, taking a long range view, if the back ward classes are helped to march forward and take their place in line with the advance sections of the people."

Thus a solid statutory base has been established for implementing the reservations for S. C./S. T. in our country. But the results of this implementation are totally distressing. Let me quote the Commissioner for SC&ST who made specific and clear observation in 1973-74 Report in page 97, stating that "There has been no substantial improvement during the preceding three years in the case of SC&ST and their representation especially in Class I and Class II services is still below the prescribed percentage." The prescribed percentage is 15 per cent for SCs and 7.5 per cent for STs. I shall show you now the glaring facts of their representation. The employment position in India as on 1st January, 1976 would make us very clear to understand the percentage of employment of these people The percentage of SCs in Class I services is 3.46; in Class II, it is 5.41; in Class III, it is 11.31 and in Class IV it is 18.75. In the case of STs, the percentage of representation in Class I is .68, in Class II, it is .74; in Class III it is 2.51 and in Class IV it is 3.93.

If we go a little further in order to examine the relative total strength in the Class I and Class IV services that would enable us to understand the rate of growth and the direction of growth. As on 1st January, 1976, the total number of SCs is 1287 in Class I services whereas in Class IV services excluding scavengers and sweepers ,it is 2,30,723. In the case of STs, their total number in Class I is 253 and in Class IV it is 48,322. This makes us very clear to understand that the rate of growth is stagnant at the higher level but at the lowest level, it is not so.

If you go a little further to examine this position in the public sector, it is still more clear. According to the Director-General of Employment and Training, the number of vacancies reserved from the total number of vacancies notified in the employment exchanges accounted for only 5.7 per cent against 15 per cent for SCs and 2.2 per cent against 7.5 per cent for STs. These 15 per cent and 7.5 per cent have been prescribed by the Ministry of Home Affairs. Here the curious fact is that even out of this meagre number of reserved vacancies less than half of them are filled up and the rest were left unfilled. If you go to examine this matter in All-India Services, it is still more clear that as on 1st January, 1976, the total number of IAS officers in India is 3235 out of whom the representation of SCs is 277 instead of 450 which the minimum reserved quota guaranteed by the Constitution. In the case of STs it is 132 instead of 200 which the minimum reserved quota. In the case of IPS, the total number of IPS in India is 1761 out of which the STs. representation is 147 only instead of 247 and STs representation is 52 only instead of 104.

If we go to examine this position in the judiciary in India, it arrests our attention that in the entire country of our 18 High Courts out of 22 States consisting of 351 judges including 64 vacancies excluding 13 judges of the Supreme Court, there is not even a single representation from the STs except the microscopic minority of 5 judges from SCs..

In the history of the Supreme Court neither chief Justice nor justice ever has been from these classes of SC/ST.

Now, let us examine this position in the P&T Department, the Director-General of Posts and Telegraphs recently in May, 1977 has effected promotions of 500 junior engineers from Class III cadre to Class II cadre while giving promotion only to 12 candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes instead of more than

[Shri Kusuma Krishna Murthy]

75 which is their minimum reserved quota. The curious fact here is that there are more than 100 eligible candidates for promotion from SC/ST. This representation has been received by me from Mr. V. Vamanadas, Founder President of Ambedkar Abraham Lincoln Mission of Vijawada. wada.

Another interesting representation that I have received from Mr. Achleswar Parihar from Gujarat. He is a Scheduled Caste employee. He is the Traffic Inspector in the Western Railway. After putting in 27-1/2 years of meritorious service with awards, he was given reversion orders from the cadre of Rs. 550 to Rs. 330. As per his version, he has been victimised only because he happens to be a Scheduled Caste man and also he happens to be representing a welfare association ventilating the grievances of the people.

Above all, in the entire Central Secretariat in New Delhi there is not even a single Secretary either from the Scheduled Caste or from the Scheduled Tribe even after 30 years of independence, except an Additional Secretary and only a Joint Secretary. This is the position existing in India today.

Yesterday, my hon. friend, Shri Kanwar Lal Gupta was saying that there are so many provisions and safeguards provided in the Constitution for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. I agree there are provisions in our Constitution, there are safeguards in our Constitution, there is a time gap of 27 years and, above all, there is the Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in this country. In spite of all these things, there is a baffling back log of un-filled up reserved seats de-reserved in every category of service in India as on today.

Basing on all these facts, Chief Justice K. Subba Rao in his dissenting judgment in the case of Devadasan Vs. State of Mysore, clearly observed that "there is no objection to making reservation on the total strength of the cadre instead of making reservation on the basis of maintenance vacancies." But the Department of Personnel and Administrative Reforms has clearly stated in their Report for the year 1973-74 that they are providing recruitment "in relation to the vacancies arising from time to time, not on the basis of the total strength of any cadre or service."

Again, in this connection, the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has made a significant observation that if this kind of situation goes on, "they will never be able to catch up in the matter of their representation in proportion to their respective population in this country unless enhanced percentages of reservation are provided for." Here, the Commissioner, has missed an important point. It is not the question of enhancing the percentage of reservation that is important first it is the question of removal of hindrance for implementing these reservations which is more important now.

In fact, it is the article 335 which is coming in the way of implementing reservation properly. There is a qualifying clause in article 335, that is, "with due regard to the maintenance of efficiency." The expression "with due regard to the maintenance of efficiency" contained in article 335 which is a supporting article to article 16 (4) of our Constitution has been expolited against the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes simply by laying emphasis only on the efficiency, not on the purpose nor on the spirit of this article. In the name of efficiency, the candidates qualified in the examination and called for interview have been rejected and the employees who are eligible for promotion have been detained.

There is another important clause, that is "suitability" clause. That is also playing a mischievous role. Besides, the judiciary is silently nulli-

fying the reservation orders. There is also the principle of "confidential report" and over-dependence on confidential reports is absolutely erroneous as long as Caste system exists in India. This principle must be replaced by "the open-performance chart."

These are all very important factors which have contributed for the reserved vacancies to be de-reserved. The principle of de-reservation is a paradox in its. If Dereservation is really a leakage. It is just like pumping in and pumping out—water of the same volume through the same valve—the valve is article 335.

Here, again, the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has taken much pains to discuss at length as to whether the provisions of article 335 are mandatory or directory. This is absolutely irrelevant because in the light of our experience and results, it should be either scrapped or amended.

I would, therefore, suggest to the hon. Minister to take this matter into serious consideration forthwith. This qualifying and elusive clause "with due regard to the maintenance of efficiency" should be replaced by the expression "with due regard to only prescribed qualification" so that injustice can be avoided. Only after this, the pricple of proportional representation on the Basis of the total strength of the cadre must be expediently and immediately implemented so that social justice can be attained "genuinely", the word on which the present Government is laying much emphasis "Genuineness" in its implication and implementation is very significant in internal matters rather than in external policies of a Government.

Now I will come to the economic aspect of the SC&ST. The Scheduled Castes are 80 millions and the Scheduled Tribes are 40 millions. Most of them are labourers and they contribute to the capital growth of our country by way of their labour and by way of indirect taxes. After all, *capital is the exploited labour.* So, for the formation of capital labour is a very significant factor. For the growth of our national economy, these SC&ST contribute a substantially day in and day out but the allocations ear-marked for their betterment are always quite insignificant and meagre.

If we look at the allocations of the Five Year Plans starting from the First Plan, the fact is quite clear. Rs. 4000 crores but, for the betterment The total amount earmarked for the First Plan was about Rs. 2000 crores but the allocation ear-marked for SC *was only 1.5 per cent of it. In the* case of the Second Plan, the total amount ear-marked was about of SC/ST people, only 1.6 per cent was allotted. In the Third Plan, the total amcunt ear-marked was about Rs. 8000 crores out of which only 1.1 per cent was allotted for the betterment of these SC/ST classes. During the annual plans, out of the total amount of more than Rs. 6000 crores, only 1 per cent was allotted to SC/ST classes. In the Fourth Plan, out of about Rs. 16,000 crores, only 1 per cent was allotted to SC/ST classes. And during the present Five Year Plan, out of the total allocation of more than Rs. 39,000 crores only 1.3 per cent has been ear-marked for the betterment of SC/ST classes. This fact makes us very clear to understand the attitude of the Government towards the betterment of these classes during all these 27 years so far in this country.

There is a general impression that the overall and general growth of national economy would also bring up the economic status of these SC/ST classes simultaneously, but this has been proved absolutely wrong.

This fact can be clearly established by taking into consideration the *per capita income* in India *The per capita* income in 1947 was Rs. 228 whereas in 1975-76, it has risen to Rs. 1004.9 and it accounts for Rs. 2.75 paise per head per day in India. But the 95 per cent of SC & ST who are still *living much below the poverty line*

[Shri Kusuma Krishna Murthy]

with very much less than a rupee income per day would speak clearly about the growth of their economic status even after all these five year plans. This is a significant fact to be borne in mind.

Another significant factor that comes in the way of their economic growth is the caste system, which does not allow them to diversify themselves in different trades and business. Dr. Ambedkar emphatically said; "in our political structure, we recognise one man one vote, one vote one value. But in our economic and social structure, we deny this principle of one man one value", because the value of a person is fixed by virtue of his being born in a caste in India. There are 3000 castes in India out of whom 300 are brahmin sub-caste among whom there is neither inter-dinning nor inter-caste marriages. And this situation in India is still worsening because the social mobility is confining itself to narrow limits of sub-castes.

The weaker-sections are in explosive force; unless their economic status is substantially improved to bring them on par with the rest of the society in all aspects they would blow off any structure anywhere. This is an historical fact.

Our renowned economist, Dr. V. K. R. V. Rao has clearly emphasised the fact that in India there is no "functional mobility" among castes in matters of trade and business. Certain castes have been allowed to do some specific trades and businesses whereas in the case of SC & ST the menial services are reserved for them. For instances, the services of scavengers and sweepers are exclusively became the 'monopoly houses' of the SC & ST because no other caste is competing to enter into these monopoly houses.

I. therefore, request the hon. Minister to bring in an immediate legislation to prohibit carrying the night soil on the heads of the Harijans in India and to introduce mechanisation for these services throughout India. In this connection, I would request the Governcent to see that more and more financial allocations are earmarked separately specially for the betterment of SC & ST in India; and secondly, the Government should bring in an immediate legislation for introducing functional mobility in our economy soon. Unless there is functional mobility, there would be no real balanced growth of economy in our country.

The other important issue is regarding the Commission for SC & ST. In 1967, the Government abolished the offices of the Deputy-Commissioners for SC & ST. At that time, "the Elayaperumal Committee, the Shilu AO Committee and the Parliamentary Committee for the welfare of SC & ST have deeply regretted and expressed their resentment about the withdrawal of these offices and requested the Government to revive these offices immediately. But nothing has been done. And again in 1969, the Commissioner for SC & ST put up a proposal to introduce 18 regional offices throughout India to enable this office to function effectively. The Commissioner insisted on having a better organisation and staff in order to enable him to discharge his responsibilities effectively and usefully, and in his own words, he requested for "eyes and ears" for this office. I can add one more thing, that is, besides "eyes and ears," "teeth" must also be required. Unless appropriate powers are also given, this Commission cannot be effective. I, therefore, request the hon. Minister to immediately see that these regional offices throughout the country are opened and see, thereby this Commission for SC & ST is functioned effectively for the real service of these classes. In this connection, I would like to focus the attention of this hon. House to an important issue, that is,

the Union Government proposes to amalgamate this office of the Commissioner for SC & ST with the proposed Civil Rights Commission, but this is absolutely an unwise step, because there is a wide contrast between the constitutional terms "backward classes" embracing SC and ST and the Constitutional term "minorities" embracing linguistic, religious and ethnic minorities. Here, the problem is absolutely different in nature, whereas in the case of SC & ST it is social and also economic, because these classes have been socially exploited for several centuries, besides economically exploited. Whereas in the case of minorities, it is different; they are only economically exploited. So, there cannot be any correlation between the problems of these two classes. There can be a separate Commission for the minorities for their betterment.

Probably, the Government is trying to equate this issue with the Commission on Civil Rights in the USA created by Civil Rights Act of 1957. Their problem in the USA is only of racial discrimination and colour prejudice. Here, it is a problem of untouchability. Here, whether he is red or black, good or bad, educated or uneducated, wise or unwise, is untouchable. So, apart from this, if this amalgamation is effected between these two, the minorities are also claiming for reservation, which is totally not acceptable. Then this amounts to scrapping of the existing reservation. Probably, this would be a device sought to extinguish the existing safeguards for SC & ST by 1980. Besides, the other important issue is the Buddhists and Harijans Christian converts, who are also equally suffering from all these social disabilities of Harijans. Therefore, it is not the religion, but these social disabilities and economic backwardness which should be the criteria for extending the reservation facilities for these classes also. In this connection, the justification far enhanced reservations for them must be taken into consideration along with their respective total strength of population in this country.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please try to conclude.

SHRI KUSUMA KRISHNA MURTHY: The other important issue in this matter is the atrocities committed on Harijans in India. I would not like to go into all the details because there are so many instances of atrocities still very green in our memory; I would only quote two instances and reserve my comments on them; and I would leave it to the hon. House to think about them, only on the basis of human being as human being.

the first instance.....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Giving instance will take more time. Please try to conclude.

SHRI KUSUMA KRISHNA MURTHY: I will finish. This instance happened in Saharsa district of Bihar where four Scheduled Caste ladies were stripped naked and branded all over their bodies with red-hot iron sickness and rods in the presence of a huge crowd of other caste Hindus.

The other instance was in Parabhani district of Maharashtra. Two Scheduled Caste women were stripped naked by a landlord and his servants on their begging for drinking water.

More shocking and shuddering was the fact that, when this ugly incident was reported to a Member of Parliament—and that too a lady Member of Parliament—She, instead of condemning such a shameful act, asked the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes to find out the character of those women. Finally it was revealed that both the women were simply innocent and women of good character.

Thus, this Commission, having absolute Constitutional validity, never seemed to function in the spirit of the Constitution. It functions more like a bureau of collecting data rather than a Commission to dissect the problems fearlessly to save and shape the des-

[Shri Kusuma Krishna Murthy]

tinies of the millions of the down-trodden in this country. It is an issue of "human dignity," not merely of Harijans upliftment, as abonimable communal cruelties still continue to be perpetrated against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the land of their own birth. It is also an issue of fraternity because without fraternity, liberty and equality will be no deeper than coats of paint.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will call the next speaker. He does not seem to conclude.

AN HON. MEMBER: He will conclude in a minute.

SHRI KUSUMA KRISHNA MURTHY: Government never seem to realise the spirit of the Constitution either in allowing this Commission to function worthy of its mission or in implementing what little the Commission has offered so far by way of suggestions. Therefore, I would like to make a humble submission through the Chair to the hon. House representing enlightened intelligentsia of this great nation that let the Government not feel complacement about this much-neglected problem of Scheduled Castes and Scheduled Tribes because complacence has ruined more nations than the sword.

श्री रामानन्द तिवारी (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर आज सदन विचार कर रहा है यह एक ऐसा विषय है कि जिसके अन्दर हमारे भाल पर, हमारे ललाट पर कलंक का टीका लगा हुआ है। 1932 में जब पूज्य महात्मा जी ने यरवदा जेल में अनशन किया था, तीन दिनों तक ऐसा लग रहा था कि सारा भारत धू-धू करके जल रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि भारत और हिन्दू जाति को बचाना है तो भारत से छुआछूत और गरीबी मिटानी होगी आज हमारे लिए लज्जा की बात है कि 30 वर्ष की आजादी के बाद भी हमारी जन-जातियों और अनुसूचित जातियों की स्थिति करीब-करीब वही है जो आजादी के पहले थी।

आप देहातों में जाइए और देखिए कि आज उनकी स्थिति क्या है? वहां की आबादी में 22 प्रतिशत उन्हीं की आबादी है। पिछली सरकार ने लगभग तीस वर्षों तक हुकूमत की और इस प्रतिवेदन में यह बार-बार सरकार की ओर से कहा जाता था कि हरिजनों और आदिवासियों का जीवन-स्तर ऊंचा उठ रहा है। लेकिन मुझे याद है, क्योंकि मैं देहात का रहने वाला हूं, देहाती जीवन से संबंधित हूं, बचपन में देखा करता था कि ये अभागे हरिजन किसी ऊंची जाति के दरवाजे पर जाते थे तो उन्हें बाहर ही अपने जूते खोल देने पड़ते थे, छाता ले कर नहीं चल सकते थे। आज उसमें कमी जरूर हुई है। लेकिन उसका उन्मूलन नहीं हुआ। आज भी अधिकतर मन्दिरों में हरिजन प्रवेश नहीं कर पाता है। आज भी कहीं-कहीं ऊंची जाति के कुओं पर उसको पानी नहीं भरने दिया जाता।

कदम-कदम पर महात्मा गांधी का नाम लेनेवाली सरकार, जिस ने 30 वर्षों तक हुकूमत की, मैं उससे पूछना चाहता हूं—आप ने कौन सा क्रान्तिकारी काम किया? सरकार ने उनके लिये न्यूनतम मजदूरी (मिनियम वेज) निर्धारित किया था, लेकिन मैं निश्चित रूप से आप को बतलाना चाहता हूं कि जो मिनियम वेज उस सरकार ने निर्धारित किया था, शायद ही कहीं मिल पाता हो। मैं बचपन में देखता था कि आम की गुठली, जो हम लोग खा कर फैंक देते थे, वह उसको उठा कर ले जाता था और उसको पीस कर, उसमें नमक मिला कर उसकी रोटी पकाता था। आज भी वे अभागे हरिजन जब दौनी के दिन होते हैं—चैत और बैसाख के दिनों में जब रबी की दौनी होती है—जानवर जो गेहूं, चना या जो खाते थे और उनके गोबर के साथ जो फुला हुआ गेहूं, चना और जौ निकलता है, उसे उठा कर ले जाते हैं, पानी में धो कर आज भी उसे खाते हैं।

मैंने बिहार विधान सभा में 24 जून, 1953 को यह बात कही थी। हमारे यहां एक माननीय सदस्य थे जो कोयला खदान के मालिक थे, श्री रुस्तम चौहान, उन्होंने कहा—"अध्यक्ष जी, जानवर के पेट में गेहूं, चना कहां से आयगा।" मैंने कहा—"चौहान जी, जरा मेरे साथ उत्तर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में दौनी के दिनों में चलो, तब आपको इसकी सत्यता मालूम होगी।"

श्रीमन, मैंने बचपन में देखा था—जब वृद्ध लोगों का निधन हो जाया करता था, तो उन के श्राद्ध के दिन अभागे डोम लालाचित आंखों से उनके दर्वाजे की ओर देखते रहते थे, ताकि जो झूठा बचा हुआ भोजन बचे उसको ले सकें। अभी कुछ दिन पहले मुझे देहात में एक श्राद्ध में जाने का अवसर मिला। मैंने देखा कि एक मासूम बच्चा और उसकी वृद्ध अभागी मां पानी में भीगते हुए झुठे पत्तलों की ओर देख रहे थे। यह स्थिति आज भी तीस वर्ष की आजादी के बाद है—बतलाइये, आप ने कौन सा काम किया है।

आप जाइये—छोटा नागपुर में—आदिवासियों की जमीन को हड़प लिया गया है, आज उनके पास बसने के लिए घर भी नहीं है। आपने आवासीय-जमीन का पर्चा उनको दे दिया है लेकिन दूसरी तरफ़ जो तथाकथित जमीन का मालिक है, उसने उन पर सिविल केस दायर कर दिया है, दीवानी मुकदमा लड़ते-लड़ते वह आदिवासी थक कर गिर पड़ा है फ़िर भी उसके साथ न्याय नहीं होता है। इसका कारण क्या है? क्या कभी आपने इस पर विचार किया है। मैं आप से पूछना चाहता हूं—आप ने कानून बना दिया है. . .

गृह मन्त्री (श्री चरणसिंह) : तिवारी जी, वे जो उधर बैठे हैं, इसका जवाब देंगे।

श्री रामानन्द तिवारी : मैं जानना चाहता हूं—आप ने देहातों में बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने का ऐलान किया—लेकिन क्या किसी हरिजन और आदिवासी को ऋण मिलता है? उनको शादी विवाह और किसी चीज के लिए भी ऋण नहीं मिलता क्योंकि महाजन उन्हें ऋण नहीं देते। आज वह हरिजन कर्ज के लिए तड़पता है और उसे कर्ज नहीं मिलता। बैंक से आप ने उसको ऋण देने के लिए क्या व्यवस्था की है? एक तरफ़ तो आप ने उसका दरवाजा बन्द कर दिया, बड़े लोग ऋण नहीं देते लेकिन दूसरी तरफ़ आपने उसको ऋण देने की कोई व्यवस्था नहीं की है। आप ने इस तरह का कानून बना दिया, यह तो ठीक किया क्योंकि पहले उसका शोषण होता था और अगर वह 100 रुपये ले लेता था तो 25, 30 और 40 वर्ष तक उससे वह वसूल किया जाता था। आप ने इस चीज को बन्द कर दिया अच्छा किया लेकिन उसके ऋण के लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई, यह मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं और हम आशा करते हैं कि जब हमारी जनता पार्टी की सरकार और हमारे गृह मंत्री जी इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि इन अभागे हरिजनों और आदिवासियों को ऋण सुलभ हो और कम से कम सूद उनसे लिया जाए।

इसके बाद मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सस्ते गल्ले की दुकानें इन हरिजनों और आदिवासियों के लिए खुलवाने की आप व्यवस्था करें क्योंकि वे समाज के सब से दबे और निचले स्तर के लोग हैं। हम जानते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी इस मामले में सचेत हैं, जागरूक हैं लेकिन मैं पुनः उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी तरफ़ आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उन सस्ते गल्ले की दुकानों पर न सिर्फ गेहूं और चावल आदि ही दिया जाए बल्कि तेल, डालडा, दालें और माचिस

[श्री रामानन्द तिवारी]

और मोटे कपड़े की व्यवस्था भी की जाए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज तो उन बेचारे लोगों को मोटा कपड़ा भी सुलभ नहीं होता है। मोटे कपड़े की व्यवस्था की गई है या नहीं, यह मैं नहीं जानता लेकिन देहात में जो खेतिहर मजदूर है, जो हरिजन और आदिवासी हैं, उनके बदन पर कपड़ा नहीं है। आज आप वहां जा कर देखें तो पायेंगे कि उन को अपना बदन ढकने के लिए और ओढ़ने के लिए भी कपड़ा नहीं है। आज कुंभी-पाक नर्क और दोखज की बात कही जाती है लेकिन मेरा यह अनुभव है और मैं जानता हूं कि इन लोगों के लिए तो नर्क यहीं पर है। आज करीब भूमिहीन हरिजन और आदिवासी फटे पुराने मैले कुचैले कपड़ों में ही अपने दिन गुजारता है और उन के मासूम बच्चों के लिए भी कपड़े नहीं है। जब जाड़े के दिनों में कड़ाके की सर्दी में रात को बच्चा पेशाब करता है तो उसकी अभागी मां उस पेशाब से भीगे कपड़े को सुबह सूखने के लिए डाल देती है और रात को उसी को ओढ़ती है। इस से बढ़ कर नर्क की कल्पना और क्या हो सकती है। आज हिन्दुस्तान की 22 प्रतिशत आबादी इस कुंभीपाक नर्क और दोखज में रह रही है। हमारा ध्यान इस तरफ़ जाना चाहिए। 30 वर्ष तक कांग्रेस सरकार ने उस तरफ़ कोई ध्यान नहीं दिया है और अब हमारा यह कर्तव्य है कि हम उन की तरफ़ ध्यान दें। मेरा निजी अनुभव है और मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं बिहार प्रान्त में विशेषकर भोजपुर और शाहबाद जिलों में नक्सलाइटस के नाम पर दर्जनों हरिजनों को परेशान किया गया और उन के खिलाफ़ लूट का कलंक लगाया गया। मैंने खुद उस की जांच की है और इस बारे में स्टेटमेंट दिया है और लिखा-पढ़ी भी की। वहां मजदूरी बढ़ाने की बात है। जिन मजदूरों का शोषण होता आ रहा है और हजारों वर्षों से होता आ रहा है वे जब अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो उनको गोली मार दी जाती है नक्सलाइट कह कर। जो यह समझते हैं और ठीक भी है कि उनको धोखे में रखा गया है, जो यह समझते हैं कि हम पददलित हैं, हमारी किस्मत में भगवान ने यही लिख दिया है और जो इस तरह से रह रहे हैं उन में आज जागृति आ रही है, खेतिहर मजदूरों, हरिजनों आदिवासियों में चेतना आ रही है, वे सचेत हो रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि कम से कम उनको दो जून मोटा अन्न खाने के लिए दिया जाए, मोटा कपड़ा पहनने के लिए दिया जाए और रहने के लिए थोड़ी बहुत जमीन दी जाए। इसका परिणाम क्या हो रहा है? दस वर्ष से जो नक्सलाइटस की बात कही जाती रही है, ऐसा इनको घोषित करके गोली मार दी जाती रही है। जो हरिजन खड़ा हो कर मांग करता था कांग्रेसी राज्य में उसको पुलिस गोली मार देती थी। भोजपुर जिले में आज भी यही हालत है कि सात आठ आदमी जो हरिजन थे उनको निर्ममतापूर्वक मार दिया गया है; इस तरह से दर्जनों मारे गए हैं। मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं। हम नहीं चाहते हैं कि देश में हिंसा हो, बहुत बड़ी क्रांति हो। अभी एक जनक्रांति हुई है मानव जाति के इतिहास में। यह क्रांति महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी के बताए हुए मार्ग पर चल कर आज तीस वर्ष के बाद हुई है। जनता पार्टी के हाथ में राज्य आया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता पार्टी की सरकार सब से पहले इन दीन दुखिया गरीब हरिजनों आदिवासियों आदि को कम से कम मनुष्य बनाने का प्रयास करेगी, जिन को भर पेट खाना नहीं मिलता है उन्हें खाना देने की व्यवस्था करेगी।

आप लैंड सीलिंग एक्ट को लें। आपात स्थिति और उसके पहले भी कांग्रेस सरकार ने बहुत प्रचार किया था और बहुत आंकड़े दिए गए हैं कि कितनी जमीन भूमिहीनों को दी गई है। उसने कहा था कि जो फालतू जमीन निकलेगी वह इनको दी जाएगी और कितनी दी गई है इसके आंकड़े भी वह सरकार समय समय पर देती रही है। मैं बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति आपके सामने रखना चाहता हूं। बार बार इस बात का प्रचार किया गया कि वहां जमीन बटेगी, जमीन उसकी होगी जो जमीन पर हल चलाता है, जो जमीन पर खेती करता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1949 में पूज्य महात्मा गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में वहां उन से ताल्लुकेदार मिले थे और जिस से आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी अच्छी तरह से परिचित हैं उस मीटिंग में उन्होंने कहा था ताल्लुकेदारों की जमीन का बटवारा करो, तुम्हारे काम से अधिक यदि तुम्हारे पास जमीन है तो उस जमीन को तुम भूमिहीनों को दे दो। इस पर ताल्लुकेदारों ने कहा था कि मान लो कि यह जो जमीन हमारी है, हम नहीं देते हैं तो इस पर महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि स्वेच्छा से नहीं दोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब भूमिहीन जो खेती करते हैं, जो अधपेट रहते हैं वे बगावत करेंगे और बगावत करके उस जमीन पर अधिकार कर लेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि देश में हिंसा हो, खून की नदियां बहें। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप पांच सात काम तत्काल करने की व्यवस्था करें।

पहला काम तो यह है कि हर हरिजन और आदिवासी मुहल्ले में आप सस्ते गल्ले की दुकान खोलें जैसे मैं बता चुका हूं जहां पर कपड़ा आदि सब चीजें सुलभ हों।

जहां पर मिनिमम मजदूरी निर्धारित की गई है उसको गृह मंत्री जी चाहें तो उस पर दोबारा विचार करें और उस में उचित समझें तो संशोधन करें और अगर वह यह समझते हैं कि वही रहनी चाहिए तो मैं निवेदन करूंगा कि उसको कार्यान्वित कराने की वह व्यवस्था करें, सख्ती से उसको कार्यान्वित कराएं। जो मिनिमम मजदूरी नहीं देता है उसको केवल जुर्माना ही नहीं देना पड़े बल्कि उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने की व्यवस्था की जाए।

आज जो हरिजनों और आदिवासियों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं वे समय पर नहीं मिलती हैं और जो मिलती हैं व बहुत ही कम हैं। इसलिए उस में वृद्धि की जाए और समय पर दिलाने की व्यवस्था की जाए।

सबसे ज्यादा लज्जा की बात यह है कि तीस बरस से कांग्रेस हकूमत ने भी जो यह व्यवस्था की थी इनके लिए सरकारी विभागों में नौकरियां सुरक्षित की जाएं, उनको भी किसी भी विभाग में और किसी भी कलास में एक से लेकर चार तक पूरा नहीं किया गया है। इन हरिजनों और आदिवासियों के लिए जो कोटा निर्धारित किया गया है उसको पूरा किया जाना चाहिए। आप देखें कि सरकार के किसी भी विभाग में चाहे रेलवे हो, आरक्षी विभाग हो, न्यायपालिका हो या कोई और विभाग हो कहीं भी उन्हें कोटे के हिसाब से स्थान नहीं दिए गए हैं। मेरा गृह मंत्री जी से निवेदन है कि वह उसे अविलम्ब पूरा करें, जो कमी है उसकी तुरन्त पूर्ति करवाएं और इनका कोटा पूरा करने के बाद ही और लोगों को भरती किया जाए।

[श्री रामानन्द तिवारी]

एक अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि समान अवसर की बात जो की जाती है वह एक धोखा है। समान अवसर से इनका उत्थान होने वाला नहीं है। मान लें किसी को आपने सवारी के लिए घोड़ा दे दिया और वह दौ सौ मील की स्पीड से दौड़ता है और इनको भी दे दिया और इनको दौ सौ मील पीछे खड़ा कर दिया और ये पीछे हैं ही तो ये कभी भी उसके बराबर नहीं आ सकेंगे। ये चार सौ मील जाएं और दूसरे दौ सौ मील जाएं तब काम चल सकेगा और तब उस स्थिति में समान अवसर का कुछ महत्व हो सकता है। स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया ने इसका बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया था और कहा था कि ये हरिजन, आदिवासी पिछड़े हुए लोग जो सदियों से शोषित रहे हैं, पीड़ित रहे हैं, जिन को हम ने मानव नहीं बनने दिया है, इन्सान नहीं बनने दिया, इनके लिए यदि समान अवसर की बात की जाती है तो यह एक धोखा है, यह एक पाखंड है। यह नाटक है। इसलिए इन्हें विशेष अवसर देने की बात डा० लोहिया ने सुझायी थी। मैं गृह मंत्री जी से आशा करता हूं कि इन पिछड़े हुए लोगों को, हरिजनों और आदिवासियों के लिए आप विशेष अवसर दें जैसा डा० लोहिया ने कहा था कि कम से कम कुछ दिनों तक 60 प्रतिशत स्थान इनके लिए सुरक्षित रखो और अविलम्ब इसकी पूर्ति करो। विशेष अवसर देने की बात जो डा० लोहिया ने कही वही मैं आज सदन में कहना चाहता हूं। यह किसी पार्टी की बात नहीं है, पार्टी पौलिटिक्स की, राजनीति की बात नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की बात है। क्योंकि जिस राष्ट्र के ललाट पर कलंक का यह टीका रहेगा, जिस गांधी जी ने कहा आजादी के बाद इस कलंक को मिटाओ तब तक हम अपने को स्वतन्त्र नहीं समझ सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब तक भारत में यह कलंक का टीका रहेगा हम अपने को स्वतन्त्र नहीं समझेंगे। इसलिए इस कलंक के टीके को धोने के लिए आपको डा० लोहिया की बात माननी चाहिए।

यह कह कर मैं विश्वास करता हूं कि पूरा का पूरा सदन सरकार का साथ देगा और जनता पार्टी की सरकार विशेष अवसर देने पर विचार करेगी, चिन्तन करेगी। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। यहां कह कर मैं बैठ जाता हूं।

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur): Mr. Deputy Speaker, Sir, I will speak in Bengali.

*Sir, the preamble of the Constitution of India conveys the solemn resolve of the makers of the Constitution to secure to all the citizens of India, justice, social, economic and political. This was what we had promised to the nation when after long years of fight we attained our political freedom and it is time that we ponder and look back to see how far and how best we were successful in implementing this solemn resolve Even after 30 years of independence we have 20 per cent of the population who belong to the scheduled castes and schedule tribes, who have no social equality, no political and no economic equality *vis a vis* the rest of the population of the country. It is a blot on our nation. It is a stigma and a matter of national shame. A great multitude of these unfortunate

*The original speech was delivered in Bengali.

people live in the villages who are agricultural workers, bonded labour, share croppers, petty peasants, factory labourers, mine workers and men the class IV posts of the Municipalities and other local bodies. If we go to the villages we will find that they are victims of feudal atrocities, where the big landlords exploit them in every conceivable manner. And when we come to the cities we find the same exploitation being continued and this time by the capitalists.

15.00 hrs.

Sir, the House is currently discussing the 21st, 22nd and the 23rd reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The reports deal with the different problems that are being faced by the members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and some of the important aspects which have been discussed are (i) untouchability, (ii) cases of atrocities and harassment, (iii) indebtedness and bonded labour, (iv) land—agriculture and forest and (v) employment. Despite the efforts of the erstwhile Government who were in ower for 30 long years, a hurried study of the reports in are now here near our goal and we are no where near our goal and we have not succeeded in creating an impressive dent in to the massive problem that confronts us. As I have said we have failed to raise the standard of living of these peoples in any substantial way nor we have been able to eradicate the social ills which have a strangle hold on them. The reasons are not far to seek because the 20th report of the Commissioner gives the reasons for the unsatisfactory progress of the schemes for the welfare of scheduled castes and scheduled tribes which are as follows:

1. General lack of a sense of urgency on the part of those responsible for the implementation of the scheme;
2. Insufficient financial provision for the welfare schemes due to low priority accorded in the various five-year plans; and
3. Lack of people's participation in the implementation of the schemes particularly due to the lukewarm attitude in this respect on the part of the political parties and want of revolutionary urge and zeal on the part of social workers.

It is indeed regrettable that such a human problem did not gain and nor could create a sense of urgency among the erstwhile rulers nor could they make suffiicent funds available for the schemes and finally they failed to enthuse the people to take up the job of eradicating the social ills in a befitting manner. The net result of all these is the pitiable position in which we have allowed the 20 per cent of our population to languish and rot.

Many hon. members of his House have narrated the banes of untouchability and the sufferings of the cheduled castes and scheduled tribes population of our country but I cannot resist mentioning a few. At page 2 of the 21st report a grim account of atrocities appear. In village Saharsa in Bihar 4 scheduled castes ladies were stripped naked and branded with red hot iron sickle all over their bodies by a large number of non-scheduled caste population and the only crime that these 4 scheduled caste ladies had committed was that they wanted to carry drinking water from a well which was in the locality inhabited by the non-scheduled castes people. An hon. member from Maharashtra has already said about the case where two scheduled caste women had to suffer the abject humilation of being stripped naked before the landlords and his servants for trying to fetch drinking water from a particular well in the village in the district of Prabhani in Maharashtra. Again in Maharashtra in the village of Aurangabad 12 innocent scheduled

[Shri Krishna Chandra Halder]

caste persons died because they were forced to drink polluted water from a well because the local caste Hindus did not allow them to take drinkable water from their well. I can go on narrating such instances of atrocities. The hon. Home Minister is present in the House. Even in the State of U.P. the report says that discrimination has been found existing against scheduled cases constables in the district police lines in the matter of messing facilities. Yesterday while taking part in the discussion an hon. Member from U.P. had stated how on flimsy excuses a harijan youth in a village near Ghaziabad was beaten and tied to a tree and was burnt and roasted like a pig by hanging him over the burning fire

SHRI CHITTA BASU (Barasat): The Home Minister should listen to these incidents.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: Sir the Congress Government had enforced emergency in this country and during this period the Government had initiated a 20-point programme to help the landless labourers but far from helping them the programme in effect instigated and infuriated the landlords who treated the harijans with such cruelty that many died and I would with your permission, Sir, quote a few lines from the Times of India dated the 26th June 1977 which *inter alia* says, in Bihar only, "In 1976, upto September, as many as 57 harijans, adivasis and members of minority communities were done to death. There is a record number of 1133 atrocities on these groups." The sume paper gives accounts of two more incidents which I would like to tell you Sir, Dev Kumar Majhi, aged 23, worked some where in Punjab and had gone to his village Gajiapur in Ekma thana of Saran district in Bihar for securing a patta for his homested lands. After he secured the *patta* the landlords beat him up mercilessly and even district magistrate twice suggesting that Majhi suspected a threat to his life but nothing was done and on October 27, Majhi's body was found lying besides the railway track near Ekma railway station. In village Malawan, in Obrakhana the labourers had gone on strike in July 1976. In fact it was an agitation by the agricultural labourers who were demanding better wages. The strike was organised by Sheopujan Ram, a young harijan and an unemployed graduate. The strike was broken by the land owners by getting labourers from adjoining villages. Sheopujan thought of establishing a factory which could give employment to many unemployed labourers of his village. As a member of the weaker section he applied for bank loan but the day before Sheopujan was to draw the loan from the bank he was murdered in cold blood and his body was cut into pieces by a sharped edged weapon and was scattered all round his hut. One of Sheopujan's son was also attacked and injured. In its issue dated 27th July, 1977 gives a full account how the harijans were attacked by rich landlords by knives, spears and axes and even women and children were not spared. The news report says that rich landlords of Chino Egirala village in Kirshna district attacked Harijan agricultural workers on Saturday last. On Harijan worker, Maddula Subbarao, was killed on the spot and 42 others including women were injured. On investigation it was found that landlords had been terrorising the agricultural workers for quite some time because the workers were cultivating a piece of banjar land and had won the lease right on that land from the Government. There are many more such sordid incidents which are occurring almost every day in our country and if we are not told about it it is because they are not being reported of the effected persons are threatened to silence. Sir, the time at my disposal is short and I will not go into the details of such incidents but I would like to emphasise that if we really

dition of the

down trodden people belonging to the scheduled castes and scheduled tribes, then the first imperative step that should be taken is with regard to land reform. Unless this is done the lot of the landless agricultural labourers who are mostly scheduled caste people cannot be improved. With your permission, Sir, I would like to quote from p. 85 Chapter 5 of the 20th report. Speaking about the ownership of land the report *inter alia* says that it "not only improves the economic condition of a person but it also raises his social status. This is one of the important reasons why we find so much land hunger among the scheduled castes and scheduled tribes. As pointed out in earlier reports the incidence of landlessness is more pronounched in the case of these communities as compared to general population." Today the exploited, tortured and opporessed masses of the scheduled castes and scheduled tribes are trying their best to find a place in the national life and the feudal lords with connivance of the authorities are suppressing this struggle. It is a matter of great national shame that such incidents of atrocities continued to be repeated and the Government looks helpless or indifferrent towards it. The hon. Members have already mentioned how the students belonging to the scheduled castes and scheduled tribes are being discriminated against in the matter of admission to medical and engineering colleges, how the reservations made in class I, II and III services of the Central Government are not being fulfiled and I would not like to go over this issue it will amount to repetition. Sir, the hon. Shri A. K. Roy has given notice of a substitute motion. In his motion he has stated that Government should set up suitable machinery to stop planned elimination of the harijans and adivasis from employment in the collieries after nationalisation and to declare the percentage of scheduled castes and scheduled tribes in the colliery employment on the date of nationalisation as the datum level. Sir, when the collieries near Dhanbad were nationalised, the percentage of workers belonging to the scheduled caste and scheduled tribes was nearly 60 per cent whereas the present strength of such workers is only 43 per cent. This rightly shows how the poor illiterate harijans and adivasis are being pushed out of employment slowly but surely and it is very necessary that we should safeguard their interests by restoring their employment figures to prenationalisation date. This is a very good suggestion and I trust the Government will come forward to accept it for implementation

There has been no perceptable improvement in the life style of the harijans and adivasis of our country who are struggling their est to carve out a place for themselves in the national life and in fact during the past 30 year their agonies have aggravated. The problem has to be viewed as a national problem and has to be tackled at the national plane rather than as a programme of a particular political party. We cannot solve it by taking a piece meal action. It is the result of social feudal and capitalist exploitation. Mere caste struggle and elimination of caste system will not be enough, we have to take multi pronged actions. Class struggle is the only way for solution. We have to introduce land reform. We have to give the tribal people a legitimate right in the forest. In the district of Bankura, some forest land was cleared by the tribals and they had established themselves on these lands and were carrying on cultivation. Unfortunately, the Congress Government did not think kindly of the matter and they were evicted. Fortunately, however, the present Government of West Bengal have initiated action to rehabilitate them. Along with this it is also very necessary that the surplus land should be distributed among such people—a matter which has been soft peddled all through by the earlier Congress Government. To raise the living standards of such people mere fixation of

[Shri Krishna Chandra Halder]

minimum wages will not do because this is often not being implemented and it is therefore necessary that suitable machinery should be created to effect proper implementation of the scheme. Along with free homestead land free education upto college level for scheduled caste and upto post-graduate level for scheduled tribes should be ensured. But without basic change in our social, political and economic norms of our society this laudable objective cannot be solved For this it is very necessary that suitable changes should be made in the Constitution and we have to implement all welfare schemes for these neglected people with remarkable boldness and without any sense of hesitation. The problem of oppression and exploitation of the scheduled castes and scheduled tribes cannot be solved in isolation by a cast struggle but it should be tackled under a a united struggle of toiling masses in villages, towns, in factories and in the fields. We have to change the society and change the Constitution. We have to socialise all means of production and this will end casteism and exploitation. Let us therefore make a determined bid in creating a casteless and a classless society. And with these words I conclude my speech.

श्री शरद यादव (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय यह जो अनुसूचित जातियों की रिपोर्ट आई है इस पर अधिकांश लोगों ने कई तरह से अपने विचारों को व्यक्त किया है। कई तरह के सवाल उठाये गये हैं लेकिन मेरी मान्यता यह है कि जो रिपोर्ट आई है—इस तरह का प्रयास इस देश में मुझे प्राचीनतम लगता है। पिछली सरकार का भी प्रयास इसी तरह का था और उसी के तेहत ये प्रयास किये जा रहे हैं। गांधी जी के सामाजिक आन्दोलन के चलते हिन्दुस्तान में लोगों को कुछ शर्म आई और उन्होंने अपने दिमाग में यह जो कलंक है उस पिछड़े वर्ग के प्रति एक मरी हुई सहानुभति जाहिर करने की कोशिश की। तो यह मरी हुई इच्छा है और यदि यह मरी हुई इच्छा न होती तो शायद इस देश में परिवर्तन की धारा जिस पाप से ये सारे रोग निकलते हैं उस पाप की समाप्ति के लिये शायद क्रान्तिकारी कदम जरूर उठाये जाते।

22 सैकड़ा का जो सवाल लोगों ने उठाया है आदिवासी हरिजन और दबा हुआ पबका 22 सैकड़ा है—मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि इन 22 सैकड़ा आदमियों को इतना नीचे गिराने के लिये हिन्दू समाज में जिस दिन भी इस बात की रचना हुई होगी उस दिन सब से पहले कुछ लोगों के स्वार्थ के कारण आधी महिलाओं की गुलामी जोड़ी गई होगी। इन दबे हुए लोगों की आबादी 22 सैकड़ा नहीं हैं इस देश की आधी औरतें भी उसमें शामिल हैं इस देश की जाति-व्यवस्था इस देश का कोढ़, पाप जिसमें ये सारे सवाल पैदा होते हैं, उस आबादी को पैदा करने के लिये जब महिलाओं को गुलाम बनाया गया उसकी योनि के साथ चरित्र को जोड़ कर बांधा गया उस दौर में इन 22 सैकड़ा आदमियों को नीचे की ओर दबा दिया गया। मेरा निवेदन है कि ये 22 सैकड़ा आदमी जो आज दबे हुए हैं कुचले कहे जाते हैं वे आधी महिला की गुलामी को जोड़ कर दबाये गये और कुचले गये। इस तरह से जोड़-घटा करने पर आपको मालूम होगा कि 80 सैकड़ा आदमियों को पिछले पांच हजार सालों में पैदा किया जा रहा है मुर्दा बनाया जा रहा है। यानी 80 सैकड़ा आदमी ऐसे हैं—जिन में न कोई महापुरुष हुआ, न कोई वैज्ञानिक पैदा हुआ, न लेखक पदा हुआ और न बुद्धिजीवी पैदा हुआ और न कोई कवि पैदा हुआ।

तो मेरा यह तर्क है कि 80 सैकड़ा आबादी जो है, उसको 5 हजार वर्ष से पैदा करके कब्र का नजराना दिया है और इस रोग से इस देश की जो लम्बी गुलामी है, वह जुड़ी हुई है और आदिवासियों और हरिजनों का सवाल इस देश की सम्पूर्ण तकदीर के साथ जुड़ा हुआ है। यह देश जब गुलाम हुआ तो हम लोग आत्म चिंतन करें कि कैसे गुलाम हुआ।

इस के इतिहास में अगर हम जाएं तो पायेंगे कि 12 सैकड़ा आदमी ऐसे थे जिनको लड़ने की आजादी थी और वे थे क्षत्रिय। उन 12 प्रतिशत क्षत्रियों में से आधी महिला निकल गईं और चार प्रतिशत बच्चे और बूढ़े निकल गये। इस तरह से केवल 2 प्रतिशत ही जवान आदमी थे। उनमें जवानों को देश की रक्षा के लिए लड़ना था। उस समय टेक्नोलाजी और विज्ञान में भी इतनी बड़ी उन्नति नहीं हुई थी कि बंगाल का जो नौजवान था वह खैबर के दर्रे तक पहुंच जाता या दक्षिण का जो लड़ने वाला नौजवान था वह खैबर दर्रे में पहुंच सकता। मैंने गणित में गुणा-भाग करके देखा है कि उस समय .05 प्रतिशत इस पूरे देश की आबादी इस पूरी कौम की आबादी का हिस्सा ही युद्ध में लड़ रहा था। उस समय का युद्ध बाजुओं का युद्ध था। उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम आत्म चिन्तन करें तो पायेंगे कि इतनी टूटी और इतनी कमजोर कौम को गौरी और गजनी न मारता तो कोई दूसरा मारता। इस तरह से हमारे देश में गुलामी आई। सोमनाथ मंदिर के बारे में जो लोग मुसलमानों के खिलाफ़ भड़काया करते हैं, वे कभी अपनी नालायकी पर और कमजोरी पर नहीं रोते हैं और अपने पापों की ओर कभी नहीं देखते हैं। उन्होंने ही हमें गुलाम बनाया है। हम गुलाम नहीं होते अगर इस तरह की बातें न होतीं। इतिहास में शायद ही दुनिया की कोई कौम इतने लम्बे समय तक गुलाम रही हो जितनी कि भारत की हिन्दू कौम गुलाम रही है। मेरा जो इतिहास का ज्ञान है, उसकी बिना पर मैं यह कह सकता हूं कि कोई दूसरी कौम इतने लम्बे समय तक गुलाम नहीं रही। और यह गुलामी कहां से आई? इस जाति व्यवस्था से और हरिजनों को जो तोड़ कर मरोड़ कर दबाया गया उससे ही इस गुलामी का जन्म हुआ है।

आधी औरतों को हम ने गुलाम बनाया है और एक जाति को गुलाम बनाने के लिए जाति व्यवस्था जिम्मेदार है। आप इतिहास को देखें सावित्री ने क्या किया। वह अपने पति को मौत से वापस ले आई और उसको इतिहास में बहुत बड़ा चरित्र माना गया। द्रोपदी जोकि सारे महाभारत में सबसे होशियार औरत थी उसको हमारे भारत में सब से छोटा चरित्र माना गया। द्रोपदी को वह मान नहीं मिला जो सावित्री को मिला। सावित्री को इस देश की नारी का प्रतीक माना गया। यह हमारे दिमाग़ की खराबी थी। अभी श्यामा शर्मा का केस हुआ और मुझे लगता है कि वह इन्हीं के सड़े दिमाग़ की उपज है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है, मेरा दावा है कि हमारी गुलामी इसी हरिजन वाले सवाल से पैदा हुई है, दबे हुए लोगों से पैदा हुई है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो तानाशाही थी जो कल गुजर गई, जो पराजित हो गई यह तानाशाही भी इस जाति की चक्की चलते चलते पिसते पिसते और जाति व्यवस्था की मुकड़न से पैदा हुई थी बड़ी घातक थी। आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने हिस्सेदारी की थी जिन परिवारों की हिस्सेदारी थी उन तमाम परिवारों के लोग हा 30 वर्षों तक इस देश की गद्दी पर बैठे रहे। कांग्रेस के जो मेरे भाई उधर बैठे हैं वे ग़लतफहमी में न रहें। आजादी की लड़ाई में जो परिवार अगुवा थे उन्होंने ही 30 वर्षों तक राज्य किया। लोग इसको तानाशाही कहते थे लेकिन मैं सोचता हूं तो पाता हूं कि यह जो तानाशाही थी यह बड़ी कमजोर और निकम्मी तानाशाही थी और इसकी बहुत ही मरी हुई तबियत थी और जिस तरह की सड़ी हुई व्यवस्था है उसी तरह की यह तानाशाही थी। तो उपाध्यक्ष महोदय, इस चाक की चक्की और पहियों के चलते चलते यह खानदानशाही चली और आजादी की लड़ाई में जिन खानदानों की दुहाई दी जाती थी, उन्हीं खानदानों का देश में राज्य चला। देश खानदान से लेकर प्रदेश खानदान हुआ; जिला खानदान हुआ

[श्री शरद यादव]

और गांव खानदान हुआ और उन्होंने ही 30 वर्षों तक राज्य चलाया। इसके लिए मैं थोड़ा सा उदाहरण दे दूं। राष्ट्रीय खानदान, देश खानदान जो था, वह मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गांधी और संजय गांधी का था। अब उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, तो पंत साहब, कमलापति त्रिपाठी और लोकपति त्रिपाठी का खानदान है, जिनका आज बयान भी आया है। अब आप बंगाल में चले जाइए, तो वहां पर सिद्धार्थ शंकर राय है जोकि श्री चितरंजन दास के नाती हैं।

आप बिहार में चले जायें। ललित नारायण मिश्र और उनके भाई श्री जगन्नाथ मिश्र। उनके खानदान के और कौन-कौन लोग थे इसको बिहार के लोग ज्यादा अच्छी तरह से जानते होंगे। मैं अपने प्रदेश की बात अब आपको बतलाता हूं। वहां पर पंडित रवि शंकर शुक्ल थे। फिर विद्या चरण शुक्ल, फिर श्यामा शरण शुक्ल। पिछली असेम्बली में उनके खानदान के, समधी आदि कुल मिला कर 25-27 एम० एल० ए० थे। जिस शहर से मैं जीत कर आया हूं जबलपुर जहां पर डा० गोविन्द दास, जगमोहन दास और मनमोहन दास, जो मेरे खिलाफ खड़े हुए थे उनके नाती रविमोहन दास शहर स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर आप देखें तो आपको खानदानशाही का राज ही है यह चीज देखने को मिलेगा। यह खानदानशाही पैदा कैसे हुई, यह राज रोग कैसे पैदा हुआ। परिवार के मोह से यह पैदा हुआ है। इस मोह के कारण ही लोग पाप करते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी को दोष न दिया जाए। हिन्दुस्तान के खून में ही यह बात शुरू से चली आई है। अपने परिवार के लिए मोह लोगों का चला आ रहा है। उत्तर भारत का सर्वेक्षण डा० मोहन सिंह जो सोशल साइंसिस में डाक्टर हैं, उन्होंने किया था। उत्तर भारत की जेलों में जो लोग भ्रष्टाचार के आरोप में बन्द हैं उनसे उन्होंने भेंट की और उनमें से 92 सैकड़ा आदमियों ने यही बताया कि उसको बेटे की शादी के लिए, लड़की की शादी के लिए, भाई की शादी के लिए पैसे की जरूरत थी और उसको भ्रष्टाचार करना पड़ा। परिवार के मोह मे ही यह चीज पैदा हुई है। अब आप देखें कि परिवार का मोह कहां से पैदा हुआ।

यह पैदा होता है औरत और महिला को पुरुष द्वारा गुलाम बनाए जाने से। महिलाओं को गैर बराबरी का दर्जा दिया गया। लेकिन वास्तव में दोनों का दिमाग बराबर है। यह चीज आज की साइंस और टैक्नालाजी ने सिद्ध कर दी है। महिला और पुरुष के दिमाग में कोई अन्तर नहीं है। लेकिन हिन्दुस्तान की महिला को गुलाम बनाया गया और बाद में यह चक्की चली मोह वाली। एक पुरुष की सम्पूर्ण जिन्दगी में, सोशल जिन्दगी में एक लाख लोगों के सम्पर्क होता होगा लेकिन एक महिला का पूरी जिन्दगी में दो तीन हजार आदमियों से ही होता होगा। बुद्धि और विवेक दोनों में ये बराबर हैं यह चीज जर्मन साइंटिस्ट ने अभी अपने रिसर्च के आधार पर सिद्ध की है। दिमाग सब से ज्यादा बढ़ता है मैन टू मैन कांटेक्ट से। जितनी उससे ब्रेन की फैसिलिटी बढ़ती है उतनी किसी दूसरी चीज से नहीं। महिलाओं का जो सम्पर्क था उसको हमने सिकोड़ा। जब हमने उसको सिकोड़ा और महिलाओं के ऊपर जुल्म किए तो उसने समाज के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर अपना लाड उड़ेल दिया और उसने समाज को सिकोड़ कर समाज में हर प्राणी के मोह और प्यार को अपने बेटे, बेटी, बीवी में सिकोड़ कर रख दिया।

मैं कभी-कभी विचार करता हूं कि तुलसीदास जी और कबीर दास जो एक साथ पैदा हुए, तुलसीदास जी की रामायण तो रातों रात चल गई और कबीर दास जो इतने बड़े क्रान्तिकारी थे उनका नाम तक कोई नहीं लेता है। उसमें भी यह राज रोग, यह प्यार

ोग चूंकि भर दिया गया इस वास्ते उनको सब याद करते हैं और याद करके रोते हैं। उस रोग के ऊपर उन्होंने अपना ग्रन्थ लिखा। दशरथ को याद किया जाता है तो अपने बाप को याद कर रोते हैं। कभी तुल ीदास की रामायण को याद करके कोई नहीं रोता है। भरत और राम का किस्सा चलता है, सीता और राम का किस्सा चलता है तो भाई और पत्नी को याद करके आदमी रोता है, या आनन्दित होता हैं। इसलिए वह जो ंन्थ था वह रातों रात प्रचलित हो गया। कहने का मतलब यह है कि देश का यह सब रोग, मानस स्थिति, पाप, सब चीज आज भी उसी तरह से चल रही है। कांग्रेस पार्टी चली गई जनता पार्टी आई गई यह नई बोतल और पुरानी शराब वाली बात है। शराब को नहीं बदला गया है। जिसके पेट में दर्द है वही जब तक देश का नेता ऊपर आ कर नहीं बैठेगा या उसको नहीं बिठाया जाएगा कभी भी देश में कोई भी क्रान्तिकारी काम नहीं हो सकेगा, यह मेरा दावा है। देश में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा इस तरह से आंसू बहाने से, इस तरह के भाषण दे देने से और यह कह देने से कि यह सुविधा इनके लिए बढ़ाई जाएं, पैसा इनको दिया जाए। आज तक करोड़ों रुपया आपने इन पर खर्च किया है लेकिन कितना हरिजन वैलफेयर आप कर सके हैं, उस कौम के मन में कितना आपने उत्साह भरा है? सब से बड़ी बात यह है कि क्रान्ति का जब कभी बिगुल बजेगा तो वह खेतीहर मजदूर, हलवाहा, हरिजन आदि जब यह सोच लेगा, आदिवासी सोच लेगा, पिछड़ा वर्ग सोच लेगा कि जुल्म इस देश की जमीन से निकला है, जुल्म इस देश में इस देश के लोगों ने उस पर किया है, वह भी इंसान है, उसको भी जीने का और इज्जत के साथ जीने का हक है, तब ही इस देश में कोई रेवोल्यूशन या कोई क्रान्ति सफल हो सकेगी। इसके बगैर कितने ही पैसे आप दे दें सब चर जायेंगे, सब खा जायेंगे और यहां आ कर आप घड़ियाली आंसू बहायेंगे और उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। यह इसलिए मैं कह रहा हूं कि तीस साल तक हमारे देश में वोट की राजनीति चली है और इसका जो पाप है वह हम को भुगतना होगा। यदि आपने उनके पेट के दर्द को महसूस नहीं किया उसका उपचार न ीं किया, उनकी मानस स्थिति को ऊंचा नहीं उठाया तो आप याद रखें कि एक एक पाई, एक-एक छदाम आपको चुकाना होगा, देना होगा।

तो मेरा कहना है कि जो रुपया खर्च किया जाता है, सारी चीजें खर्च की जाती हैं, यह सारी चीजें जो हैं वह सब इस देश के बदमाश लोग ले लिया करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 30 वर्ष में क्या किया ? उसने हरिजनों और आदिवासियों के वोटों की खरीददारी के चलते इस देश की हरिजन कौम को एक चीचड़ बनाया और कई तरह के कमल उगाये हर प्रदेश में, और तमाम हरिजनों की कीचड़ पर 30 वर्ष तक इस देश की राजनीति चलायी है। माननीय जगजीवन राम के नाम पर कांग्रेस वालों ने सरकार चलायी। आपने 30 वर्ष तक उनके नाम पर हरिजनों को धोखा दिया है। यह जो रिपोर्ट आयी है इस रिपोर्ट के चलते. . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय यादव जी, अब आप सोमवार को बोलियेगा।

We have now to start the non-official business.

Mr. Nirmal Chandra Jain.

15.30 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

FOURTH REPORT

SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN (Seoni): Sir, I beg to move:

"That this House do agree with the Fourth Report of the Commit-